Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC | SSC | BANK RAILWAY Exam

BANKING AND FINANCIAL AWARENESS

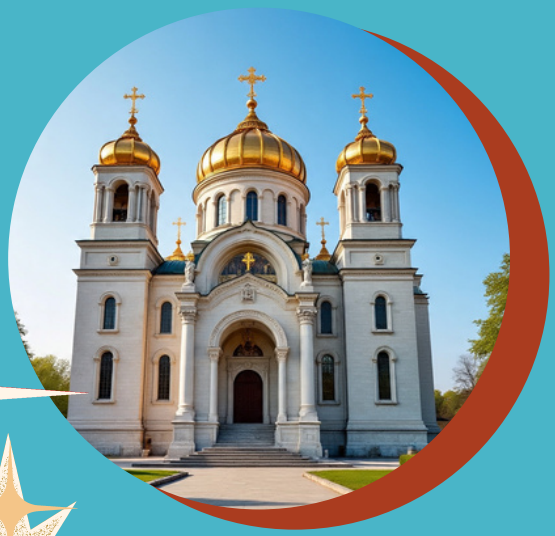

23- 29 NOV 2025

4TH WEEK OF NOVEMBER

50+ MCQ with detailed explanation

- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement

Ques: How many new names did RBI add to its alert list of unauthorised forex trading platforms?
RBI ने अपने अनधिकृत विदेशी मुद्रा)Forex) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अलर्ट लिस्ट में कितने नए नाम जोड़े?

A) 5
B) 6
C) 11
D) 8
E) 7

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) added 7 new names to its alert list of unauthorised forex trading platforms, taking the total number to 95.
• भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने अपने अनधिकृत विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अलर्ट लिस्ट में 7 नए नाम जोड़े, जिससे कुल संख्या 95 हो गई।
• The alert list includes entities that are neither authorised under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) to deal in forex nor authorised to operate electronic trading platforms (ETP) for forex transactions.
• यह अलर्ट लिस्ट उन संस्थाओं के नामों को शामिल करती है जो विदेशी मुद्रा लेन लिए के देन- अधिनियम प्रबंधन मुद्रा विदेशी, 1999 (FEMA) के तहत अधिकृत नहीं हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनके देन- लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म)ETP) संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।
• The newly added platforms are: Starnet FX, CapPlace, Mirrox, Fusion Markets, Trive, NXG Markets, and Nord FX.
• नए जोड़े गए प्लेटफॉर्म हैं :Starnet FX, CapPlace, Mirrox, Fusion Markets, Trive, NXG Markets, और Nord FX।

Ques: Bima Gram API, recently tested by IRDAI, is primarily designed to improve which of the following?
IRDAI द्वारा परीक्षण किया गया Bima Gram API मुख्य रूप से किसको बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है?

A) Urban insurance marketing / शहरी बीमा विपणन

B) Rural insurance penetration / ग्रामीण बीमा पैठ
C) International reinsurance operations / अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमा संचालन
D) Motor claim settlement / मोटर क्लेम निपटान
E) Agriculture subsidy distribution / कृषि सब्सिडी वितरण

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• The Bima Gram API, launched by IRDAI, is designed to increase insurance penetration in rural markets.
• IRDAI द्वारा लॉन्च किया गया Bima Gram API ग्रामीण बाजारों में बीमा पैठ बढ़ाने के लिए बनाया गया डिजिटल टूल है।
• The API has successfully completed the pilot testing phase.
• इस API ने अपना पायलट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
• As part of the pilot, five insurers (two life, two general, and one health) integrated, tested, and verified the API functionalities.
• पायलट में 5 बीमा कंपनियों—2 जीवन, 2 सामान्य और 1 स्वास्थ्य बीमाकर्ता—ने API के functions को integrate, test और verify किया।
• The API enables digital validation and accurate mapping of rural policies with respective gram panchayats, reduces manual paperwork, and improves accuracy, speed, and efficiency in rural business reporting.
• Bima Gram API ग्रामीण नीतियों को डिजिटल रूप से मान्य, प्रमाणित और ग्राम पंचायतों के साथ सटीक रूप से मैप करने में मदद करेगा, मैनुअल दस्तावेज़ीकरण कम करेगा, और ग्रामीण व्यवसाय रिपोर्टिंग में सटीकता, गति और दक्षता बढ़ाएगा।
• The API helps insurers build comprehensive rural datasets for future policy planning and resource allocation.
• API बीमाकर्ताओं को भविष्य की नीति योजना और संसाधन आवंटन के लिए मजबूत ग्रामीण डेटा सेट बनाने में मदद करता है।

Ques: Which country did the UAE make its first central bank digital currency (CBDC) payment to?
यूएई ने अपनी पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी)CBDC) भुगतान किस देश को की?

A) India / भारत

B) China / चीन
C) United States / अमेरिका
D) Saudi Arabia / सऊदी अरब
E) Japan / जापान

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• The UAE completed its first central bank digital currency (CBDC) payment to China, marking a major milestone in global financial connectivity.
• यूएई ने चीन को अपनी पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी)CBDC) भुगतान पूरी की, जो वैश्विक वित्तीय जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
• The transaction was executed via the newly launched Jisr platform, highlighting growing strategic cooperation between the two nations in digital finance and payment modernisation.
• यह लेन गए किए लॉन्च नए देन-Jisr प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया, जो डिजिटल वित्त और भुगतान आधुनिकीकरण में दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है।
• The Jisr platform, developed with participation from Emirati and Chinese banks, enables instant CBDC-based cross-border settlements.
• Jisr प्लेटफॉर्म, जिसे अमीराती और चीनी बैंकों की भागीदारी से विकसित किया गया है, तुरंत CBDC-आधारित सीमाहै। करता प्रदान सुविधा की भुगतान पार-
• More central banks are expected to join the network as it expands in 2026.
• जैसे नेटवर्क यह जैसे-2026 में विस्तारित होगा, और केंद्रीय बैंक इसमें शामिल होने की संभावना है।

Ques: How much dividend did state-owned GIC Re pay to the Government of India for FY24-25?
राज्य वाली स्वामित्व-GIC Re ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को कितना लाभांश दिया?

A) Rs 750 crore / 750 करोड़ रुपये
B) Rs 1,445 crore / 1,445 करोड़ रुपये
C) Rs 2,100 crore / 2,100 करोड़ रुपये
D) Rs 6,701 crore / 6,701 करोड़ रुपये

E) Rs 10 crore / 10 करोड़ रुपये

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• State-owned GIC Re paid Rs 1,445 crore as dividend to the Government of India for FY24-25.
• राज्य वाली स्वामित्व-GIC Re ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को 1,445 करोड़ रुपये का लाभांश दिया।
• The government holds an 85.50% stake in the listed reinsurance company.
• सरकार की सूचीबद्ध पुनर्बीमा कंपनी में 85.50% हिस्सेदारी है।
• GIC Re recorded a profit of Rs 6,701.36 crore in FY25 and declared a final dividend of Rs 10 per equity share.
• GIC Re ने FY25 में 6,701.36 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभ दर्ज किया और प्रति इक्विटी शेयर 10 रुपये का अंतिम लाभांश घोषित किया।
• GIC Re employees have the highest per capita profit in India, with a workforce of fewer than 500 employees.
• 500 से कम कर्मचारियों के साथ, GIC Re के कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति लाभ देश में सबसे अधिक है।

About GIC Re :

- Established : 1972
- HQ : Mumbai
- CMD : Ramaswamy Narayanan

Ques: Which company received in-principle approval from SEBI to set up a Mutual Fund business?
किस कंपनी को म्यूचुअल फंड व्यवसाय स्थापित करने के लिए SEBI से इन प्रिंसिपल-मिला अनुमोदन?

A) HDFC Asset Management / एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट
B) Master Capital Services Limited / मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड
C) SBI Mutual Fund / एसबीआई म्यूचुअल फंड

D) ICICI Prudential AMC / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी
E) Nippon India Mutual Fund / निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• Master Capital Services Limited, a wholly-owned subsidiary of Master Trust, received in-principle approval from SEBI to set up a Mutual Fund (MF) business.
• मास्टर ट्रस्ट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड को म्यूचुअल फंड)MF) व्यवसाय स्थापित करने के लिए SEBI से इनमिला। अनुमोदन प्रिंसिपल-
• After this approval, the company can proceed with regulatory processes to establish an Asset Management Company (AMC) and launch mutual fund schemes, subject to SEBI's final approval.
• इस अनुमोदन के बाद, कंपनी SEBI की अंतिम स्वीकृति के अधीन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी)AMC) स्थापित करने और म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने की नियामक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा सकती है।

Ques: Who has been appointed as the Whole-Time Member (WTM) of SEBI? किसे SEBI का होल) मेंबर टाइम-WTM) नियुक्त किया गया है?

A) Ashwani Bhatia / अश्वनी भाटिया
B) Sandhip Pradhan / संधिप प्रधान
C) Amarjeet Singh / अमरजीत सिंह
D) Kamlesh Chandra Varshney / कमलेश चंद्र वर्श्नेई
E) Rajesh Kumar / राजेश कुमार

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• Sandhip Pradhan has been appointed as the Whole-Time Member (WTM) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) for a term of three years.

• संधिप प्रधान को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया)SEBI) का होल मेंबर टाइम-)WTM) तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है।
• He replaces Ashwani Bhatia in the role.
• उन्होंने अश्वनी भाटिया की जगह ली है।
• Currently, SEBI has two other Whole-Time Members — Amarjeet Singh and Kamlesh Chandra Varshney.
• वर्तमान में, SEBI के पास दो अन्य होल हैं मेंबर टाइम-— अमरजीत सिंह और कमलेश चंद्र वर्श्नेई।

Ques: TIPS, with which RBI is linking UPI, is an instant payment system operated by which region?
TIPS, जिसके साथ RBI UPI को interlink कर रहा है, किस क्षेत्र द्वारा संचालित instant payment system है?

A) ASEAN
B) Eurozone
C) SAARC
D) BIMSTEC
E) BRICS

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) is operated by the Eurosystem, which includes the European Central Bank (ECB) and central banks of Eurozone countries.
• TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) यूरोसिस्टम द्वारा संचालित है, जिसमें यूरोपीय सेंट्रल बैंक) ECB) और यूरोज़ोन देशों के केंद्रीय बैंक शामिल हैं।
• RBI has started linking India's UPI with TIPS to facilitate faster, seamless, and cost-effective cross-border remittances.
• RBI ने भारत के UPI को TIPS से जोड़ना शुरू किया है ताकि cross-border remittances तेज, आसान और किफायती हों।
• NIPL (NPCI International Payments Ltd) will partner with RBI to operationalise this integration.
• NIPL (NPCI International Payments Ltd) RBI के साथ मिलकर इस interlinking को

लागू करेगा।
• Users in both India and the Eurozone are expected to directly benefit from this linkage.
• भारत और यूरोज़ोन दोनों के उपयोगकर्ताओं को इस लिंक से सीधे लाभ मिलेगा।

Ques: From which month will AMFI start publishing separate data on Choti SIPs (₹250 SIPs)?
AMFI किस महीने से छोटी SIPs (₹250 SIPs) पर अलग डेटा प्रकाशित करना शुरू करेगा?

A) December 2025
B) January 2026
C) February 2026
D) March 2026
E) April 2026

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• The Association of Mutual Funds in India (AMFI) will start publishing separate data on Choti SIPs (₹250 SIPs) from January 2026, after Registrar & Transfer Agents (RTAs) complete the required system modifications.
• भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन) AMFI) जनवरी 2026 से छोटी SIPs (₹250 SIPs) पर अलग डेटा प्रकाशित करना शुरू करेगा, जब रजिस्टार एवं ट्रांसफर एजेंट) RTAs) आवश्यक सिस्टम संशोधन पूरा कर लेंगे।
• SEBI reduced the minimum SIP amount to ₹250 to boost retail participation, but this is not allowed in debt, high-risk sectoral/thematic, small-cap, and mid-cap schemes.
• SEBI ने खुदरा भागीदारी बढ़ाने के लिए न्यूनतम SIP राशि ₹250 कर दी, लेकिन यह डेट, उच्च जोखिम वाले सेक्टोरल/थीमैटिक, स्मॉल-कैप और मिड-कैप योजनाओं में अनुमति नहीं है।
• Due to high transaction costs, Choti SIP payments are allowed only through NACH or UPI AutoPay modes.
• उच्च लेन-देन लागत के कारण, छोटी SIP भुगतान केवल NACH या UPI AutoPay मोड के माध्यम से ही संभव है।
• RTAs must track only the first three Choti SIPs per investor (via PAN) eligible for subsidised transaction costs; additional SIPs will not receive subsidies.

• RTAs को प्रत्येक निवेशक) PAN के माध्यम से (के केवल पहले तीन योग्य छोटी SIPs को सब्सिडी वाले लेन-देन खर्च के लिए ट्रैक करना चाहिए; अतिरिक्त SIPs को सब्सिडी नहीं मिलेगी।

About Association of Mutual Funds in India (AMFI)

- Established : 1995
- HQ : Mumbai
- CEO : Chalasani Venkat Nageswar

Ques: Which financial entity plans to request RBI to allow smaller urban cooperative banks to offer digital banking services?

कौन सी वित्तीय संस्था आरबीआई से छोटे शहरी सहकारी बैंकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति मांगने की योजना बना रही है?

A) NABARD / नाबार्ड
B) National Urban Co-operative Financial and Development Corporation (NUCFDC) / राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम
C) SIDBI / लघु उद्योग विकास बैंक
D) RBI / भारतीय रिज़र्व बैंक
E) PFRDA / पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• The National Urban Co-operative Financial and Development Corporation (NUCFDC) plans to approach the RBI to allow smaller urban cooperative banks (UCBs) with net worth below ₹50 crore to provide digital banking services such as internet banking, mobile banking, and UPI.
• राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम) NUCFDC) आरबीआई से छोटे शहरी सहकारी बैंकों) UCBs) को ₹50 करोड़ से कम नेट वर्थ वाले बैंक के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति देने की योजना बना रहा है।
• Currently, only UCBs with net worth above ₹50 crore can offer digital

banking, leaving over half of the 1,462 UCBs—holding ₹5.5 trillion in deposits—unable to provide these services.
• वर्तमान में, केवल ₹50 करोड़ से अधिक नेट वर्थ वाले UCBs ही डिजिटल बैंकिंग प्रदान कर सकते हैं, जिससे 1,462 UCBs में से आधे से अधिक, जिनके पास ₹5.5 ट्रिलियन की जमा राशि है, ये सेवाएँ नहीं दे पा रहे हैं।
• NUCFDC, a mid-layer NBFC since February 2024, is developing a central digital stack for UCBs, including IT infrastructure, applications, cybersecurity, manpower, and maintenance.
• फरवरी 2024 से मध्यम-स्तरीय NBFC के रूप में NUCFDC UCBs के लिए IT इन्फ्रास्ट्रक्चर, एप्लिकेशन, साइबर सुरक्षा, मानव संसाधन और रखरखाव सहित केंद्रीय डिजिटल स्टैक विकसित कर रहा है।
• In March 2024, Union Minister for Cooperation Amit Shah inaugurated NUCFDC, an umbrella organisation for urban cooperative banks.
• मार्च 2024 में, सहयोग मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए छत्र संगठन NUCFDC का उद्घाटन किया।

Ques: According to IRDAI, by what percentage did health insurance claims rise in FY25?
IRDAI के अनुसार FY25 में स्वास्थ्य बीमा दावे कितने प्रतिशत बढ़े?

A) 12.88%
B) 18.5%
C) 21.18%
D) 25.40%
E) 30.12%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• IRDAI reported that health insurance claims surged by 21.18% in FY25, even as the settlement of claims lagged.
• IRDAI के अनुसार FY25 में स्वास्थ्य बीमा दावे 21.18% बढ़े, जबकि सेटलमेंट की गति पीछे रह गई।
• Insurers settled 3.26 crore health claims and paid ₹94,247 crore in FY25.

• बीमा कंपनियों ने FY25 में 3.26 करोड़ दावे निपटाए और ₹94,247 करोड़ का भुगतान किया।
• The total amount settled increased by only 12.88%, showing a clear mismatch between claims filed and claims paid.
• कुल सेटलमेंट राशि केवल 12.88% बढ़ी, जिससे दावे और भुगतान के बीच बड़ा अंतर दिखा।
• Rising healthcare costs, increased hospitalisation, and inefficiencies in systems are contributing factors.
• स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत, अस्पताल में भर्ती बढ़ने और सिस्टम की अक्षमताएं इसके मुख्य कारण हैं।
• ICR (Incurred Claims Ratio) lowest for standalone health insurers — signalling pressure on profitability.
• ICR (इनकर्ड क्लेम्स रेशियो रहा कम सबसे लिए के इंश्योरर्स हेल्थ स्टैंडअलोन (— लाभप्रदता पर दबाव दिखाता है।
• FY25 premium collected: ₹1.18 lakh crore, up from ₹1.08 lakh crore in FY24.
• FY25 में प्रीमियम संग्रह :₹1.18 लाख करोड़, FY24 के ₹1.08 लाख करोड़ से अधिक।
• Public sector insurers showed 103% ICR, private sector at 88.71%.
• सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं का ICR 103%, निजी क्षेत्र का 88.71% रहा।
• The rise in claims is due to higher medical inflation, increased healthcare costs, and greater use of insurance.
• इसका कारण मेडिकल इंफ्लेशन, इलाज की बढ़ती लागत और स्वास्थ्य बीमा उपयोग में वृद्धि है।

Ques: PayGlocal has received RBI's final approval to operate as which category of Payment Aggregator?
PayGlocal को RBI से किस श्रेणी के पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की अंतिम मंज़ूरी मिली है?

A) PA – Domestic / PA – घरेलू
B) PA – Cards Only / PA – केवल कार्ड
C) PA – Cross Border – Inward & Outward / PA – क्रॉस बॉर्डर – इनवर्ड और आउटवर्ड
D) PA – Wallet Based / PA – वॉलेट आधारित
E) PA – UPI Only / PA – केवल UPI

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• PayGlocal has received final approval from the Reserve Bank of India (RBI) to operate as a Payment Aggregator – Cross Border – Inward & Outward (PA-CB-I&O).
• PayGlocal को भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर – क्रॉस बॉर्डर – इनवर्ड और आउटवर्ड)PA-CB-I&O) के रूप में काम करने की अंतिम मंज़ूरी मिली है।
• This approval allows PayGlocal to process cross-border digital transactions in both directions — money coming into India and payments going out of India.
• इस मंज़ूरी से PayGlocal क्रॉसडिजि बॉर्डर-टल लेनदेन से भारत और वाले आने में भारत) सकेगा। कर प्रोसेस को दोनों (भुगतान वाले जाने बाहर
• It strengthens India's fintech ecosystem by enabling secure, compliant, and faster global payments.
• यह मंज़ूरी भारत के फिनटेक सेक्टर को सुरक्षित, नियमतेज और संगत-़ वैश्विक भुगतान सुविधाएँ देकर मजबूत करती है।
• PayGlocal works with banks and regulated entities to support global merchant payments.
• PayGlocal बैंक और विनियमित संस्थाओं के साथ मिलकर वैश्विक व्यापारी भुगतानों का समर्थन करता है।
• India is rapidly expanding its cross-border digital payments footprint, and this approval adds another strong player to the ecosystem.
• भारत तेजी से अपने क्रॉसहै रहा कर विस्तार का नेटवर्क भुगतान डिजिटल बॉर्डर-, और यह मंज़ूरी इस इकोसिस्टम में एक और मजबूत खिलाड़ी जोड़ती है।

Ques: NCDEX is preparing to acquire a stake in the upcoming CSEDEX exchange of which country?
NCDEX किस देश के नए CSEDEX एक्सचेंज में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी कर रहा है?

A) Bangladesh / बांग्लादेश
B) Sri Lanka / श्रीलंका
C) Nepal / नेपाल
D) Myanmar / म्यांमार
E) Thailand / थाईलैंड

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• NCDEX (National Commodity & Derivatives Exchange, India) is preparing to acquire a 20% stake in CSEDEX, a new commodities and financial derivatives exchange being set up in Sri Lanka.
• भारत का नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज)NCDEX) श्रीलंका के नए कमोडिटी और वित्तीय डेरिवेटिव्स एक्सचेंज CSEDEX में 20% हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी कर रहा है।
• The investment value is 70 million Sri Lankan rupees (~₹24 crore).
• यह निवेश 70 मिलियन श्रीलंकाई रुपये)~₹24 करोड़होगा। का (
• The move aims to expand NCDEX's regional presence and strengthen international commodity market cooperation.
• इससे NCDEX अपने क्षेत्रीय विस्तार और अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी सहयोग को मजबूत करेगा।
• The collaboration is based on an MoU signed earlier in 2025, with NCDEX supporting the project under a build–operate–transfer (BOT) model.
• यह साझेदारी 2025 की शुरुआत में हुए MoU पर आधारित है, और NCDEX इसे Build–Operate–Transfer (BOT) मॉडल पर सहयोग देगा।
• NCDEX will assist Sri Lanka in technical architecture, product design, training, and regulatory frameworks.
• NCDEX तकनीकी ढांचा, उत्पाद डिजाइन, प्रशिक्षण और नियम की श्रीलंका में प्रक्रियाओं- करेगा। मदद
• Sri Lanka currently has no commodity or financial derivatives exchange.
• श्रीलंका में वर्तमान में कोई कमोडिटी या वित्तीय डेरिवेटिव्स एक्सचेंज नहीं है।
• NCDEX Background: Established in 2003; regulated by SEBI; India's major agricultural derivatives exchange. It recently saw volume decline after suspension of major agri contracts.
• NCDEX पृष्ठभूमि :2003 में स्थापित; SEBI द्वारा विनियमित; भारत का प्रमुख कृषि डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। प्रमुख कृषि कॉन्ट्रैक्ट्स निलंबित होने के बाद हाल में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट देखी गई।

Ques: As per the proposed Insurance Laws (Amendment) Bill, what will be the new FDI limit in India's insurance sector?
प्रस्तावित इंश्योरेंस लॉज़ अनुसार के विधेयक (संशोधन), भारत के बीमा क्षेत्र में नई FDI सीमा क्या होगी?

A) 74%
B) 90%

C) 100%
D) 49%
E) 85%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• The government plans to introduce the Insurance Laws (Amendment) Bill in the Winter Session of Parliament to raise the FDI limit from 74% to 100% in the insurance sector.
• सरकार सर्दियों के सत्र में इंश्योरेंस लॉज़ करेगी पेश विधेयक (संशोधन), जिसके तहत बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है।
• The move aims to boost insurance penetration, attract foreign investment, and improve ease of doing business.
• इसका उद्देश्य बीमा पहुंच बढ़ाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना है।
• The Bill may also empower IRDAI to fix lower entry capital (minimum ₹50 crore) for insurers serving under-developed segments.
• यह विधेयक IRDAI को कम एंट्री कैपिटल न्यूनतम)₹50 करोड़देगा भी शक्ति की करने तय (, खासकर पिछड़े क्षेत्रों में सेवाएँ देने वाले बीमाकर्ताओं के लिए।
• Requirement of Net Owned Funds (NOF) for foreign re-insurers may be reduced from ₹5,000 crore to ₹1,000 crore.
• विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों के लिए नेट ओन्ड फंड)NOF) की आवश्यकता ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ करने का प्रस्ताव है।
• The Bill also includes provisions for composite licences, allowing insurers to sell life + health + general insurance under a single licence.
• बिल में कॉम्पोज़िट लाइसेंस की व्यवस्था भी शामिल है, जिससे बीमा कंपनियाँ लाइफ + सकेंगी। कर प्रदान तहत के लाइसेंस ही एक इंश्योरेंस जनरल + हेल्थ
• India's insurance sector is projected to grow at 7.1% annually over the next five years.
• भारत का बीमा क्षेत्र अगले पाँच वर्षों में 7.1% वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान है।

Ques: Which Indian fintech firm recently received RBI approval to operate as a full-service Payment Aggregator?
कौन सी भारतीय फिनटेक कंपनी ने हाल ही में RBI से पूर्ण-सेवा पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी प्राप्त की?

A) Razorpay / रेज़रपे
B) PayGlocal / पेग्लोकल
C) Paytm / पेटीएम
D) PhonePe / फोनपे
E) Easebuzz / ईज़बज़

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

• Easebuzz, an Indian fintech company, received RBI approval under the Payment and Settlement Systems (PSS) Act, 2007 to operate as a full-service Payment Aggregator (PA).
• Easebuzz, एक भारतीय फिनटेक कंपनी, को पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स) PSS) एक्ट, 2007 के तहत पूर्ण-सेवा पेमेंट एग्रीगेटर) PA) के रूप में काम करने की RBI मंजूरी मिली।
• With this, Easebuzz became the third payment fintech in India to hold all three PA licences.
• इसके साथ ही Easebuzz भारत की तीसरी पेमेंट फिनटेक बन गई, जिसे सभी तीन PA लाइसेंस प्राप्त हैं।
• The approval allows Easebuzz to support digital payments across online, offline, and cross-border platforms.
• यह मंजूरी Easebuzz को ऑनलाइन, ऑफलाइन और क्रॉस-बॉर्डर प्लेटफॉर्म पर डिजिटल भुगतान का समर्थन करने की सुविधा देती है।
• Easebuzz offers a full-stack payment suite, including online payments, Point of Sale (PoS) in-person transactions, UPI soundbox acceptance, and cross-border inward & outward transactions.
• Easebuzz ऑनलाइन भुगतान, प्वाइंट ऑफ़ सेल) PoS) इन-पर्सन ट्रांज़ैक्शन, UPI साउंडबॉक्स स्वीकृति और क्रॉस-बॉर्डर इनवर्ड व आउटवर्ड लेनदेन सहित पूर्ण पेमेंट सुइट प्रदान करता है।

Ques: To which fiscal year will India switch its GDP national accounts base year as announced by MoSPI?
मोसपी द्वारा घोषित अनुसार भारत अपने GDP राष्ट्रीय खातों का आधार वर्ष किस वित्तीय वर्ष में बदलने जा रहा है?

A) FY 2011-12
B) FY 2015-16
C) FY 2022-23
D) FY 2023-24
E) FY 2004-05

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) will switch the base year for India's GDP national accounts from FY 2011-12 to FY 2022-23.
• सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) MoSPI) भारत के GDP राष्ट्रीय खातों का आधार वर्ष FY 2011-12 से FY 2022-23 में बदल देगा।
• The new series is scheduled to be released on 27 February 2026.
• नई श्रृंखला 27 फरवरी 2026 को जारी की जाने वाली है।
• A base year acts as a reference year for calculating growth, prices, and national income.
• आधार वर्ष वृद्धि, मूल्य और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए संदर्भ वर्ष के रूप में कार्य करता है।
• The last major revision of the base year was in 2015, when it changed from FY 2004-05 to FY 2011-12.
• आधार वर्ष का पिछला प्रमुख संशोधन 2015 में हुआ था, जब इसे FY 2004-05 से FY 2011-12 में बदल दिया गया था.
• A high-level Advisory Committee on National Account Statistics (ACNAS) chaired by Prof. B.N. Goldar has been formed to oversee this revision.
• इस संशोधन की निगरानी के लिए प्रोफेसर B.N. गोलदार की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय सलाहकार समिति ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स) ACNAS) का गठन किया गया है।

Ques: Who has been appointed as the Part-Time Chairperson of Jana Small Finance Bank (Jana SFB)?
जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक) जाना SFB) के पार्ट-टाइम चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) R. Ramaseshan / आर .रामसेशन
B) Shikha Sharma / शिखा शर्मा
C) Chitra Talwar / चित्रा तलवार
D) Usha Anand Subramanian / उषा आनंद सुब्रमण्यम
E) Anil Kumar Singh / अनिल कुमार सिंह

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• Chitra Talwar has been appointed as the Part-Time Chairperson of Jana Small Finance Bank Limited for a term of 2 years, till 30 January 2028.
• चित्रा तलवार को जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का पार्ट-टाइम चेयरपर्सन 2 वर्ष के कार्यकाल) 30 जनवरी 2028 तक (के लिए नियुक्त किया गया है।
• She replaces R. Ramaseshan in this role.
• उन्होंने आर .रामसेशन का स्थान लिया है।
• She has been serving as an Independent Director on the bank's board since January 2020.
• वह जनवरी 2020 से बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं।

About Jana Small Finance Bank :

- Established : 2018
- HQ : Bangalore, Karnataka
- CEO & MD : Ajay Kanwal
- Tagline : Paise Ki Kadar

Ques: What is the total approved borrowing limit for India's first maritime NBFC, Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL)?
भारत की पहली समुद्री गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी, सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड)SMFCL) के लिए कुल अनुमोदित उधारी सीमा क्या है?

A) Rs 5,000 crore
B) Rs 10,000 crore
C) Rs 15,000 crore
D) Rs 25,000 crore
E) Rs 30,000 crore

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

• Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL), India's first maritime NBFC, has approved an overall borrowing limit of Rs 25,000 crore, with Rs 8,000 crore earmarked for FY25 to start operations.
• भारत की पहली समुद्री NBFC, सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड) SMFCL) ने कुल उधारी सीमा ₹25,000 करोड़ अनुमोदित की है, जिसमें FY25 के लिए ₹8,000 करोड़ निर्धारित हैं।
• To raise these funds, SMFCL will mobilise resources through banks, financial institutions, and bond issuances as per its resource mobilisation plan.
• इन फंड्स को जुटाने के लिए SMFCL अपनी संसाधन जुटाने की योजना के अनुसार बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बॉन्ड इश्यू के माध्यम से धन जुटाएगी।
• SMFCL, formerly Sagarmala Development Company Limited, is the first maritime sector-specific NBFC in India.
• SMFCL, जिसे पहले सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड कहा जाता था, भारत की पहली समुद्री क्षेत्र-विशेष NBFC है।
• The corporation was formally registered with the Reserve Bank of India on 19, 2025 and functions under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.
• यह कॉरपोरेशन 19, 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक में औपचारिक रूप से पंजीकृत हुई और यह बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।

Ques: Which country recently unveiled an official currency symbol for its national currency, the Rial?
किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा रियाल के लिए आधिकारिक मुद्रा चिन्ह जारी किया है?

A) Qatar / क़तर
B) Bahrain / बहरीन
C) Oman / ओमान
D) Kuwait / कुवैत
E) Saudi Arabia / सऊदी अरब

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• The Central Bank of Oman (CBO) officially introduced a new symbol for the Omani Rial to standardize its use across financial, commercial, and digital platforms.
• ओमान के केंद्रीय बैंक (CBO) ने ओमानी रियाल के लिए नया आधिकारिक चिन्ह जारी किया ताकि इसे वित्तीय, वाणिज्यिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर समान रूप से उपयोग किया जा सके।
• The design reflects Oman's rich cultural heritage and growing economic maturity.
• इसका डिजाइन ओमान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक परिपक्वता को दर्शाता है।
• With this, Oman joins the list of countries with a unique currency symbol, similar to India (₹), UK (£), and Japan (¥).
• इसके साथ ही ओमान उन देशों की सूची में शामिल हो गया जिनकी विशिष्ट मुद्रा का चिन्ह है, जैसे भारत (₹), यूके (£), और जापान (¥)।

Ques: What was the sales growth of listed private non-financial companies in Q2 FY2025-26?
Q2 FY2025-26 में सूचीबद्ध निजी गैररही कितनी वृद्धि बिक्री की कंपनियों वित्तीय-?

A) 5.4%
B) 5.5%

C) 7%
D) 8%
E) 10%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

• Sales growth of listed private non-financial companies rose to 8% in Q2 FY2025-26, up from 5.5% in the previous quarter.
• सूचीबद्ध निजी गैर वृद्धि बिक्री की कंपनियों वित्तीय-Q2 FY2025-26 में 8% रही, जो पिछले तिमाही के 5.5% से बढ़ी।
• 1,775 listed private manufacturing companies saw 8.5% year-on-year growth in Q2, driven by automobiles, food products, electrical machinery, and chemicals sectors.
• 1,775 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों ने Q2 में 8.5% सालकी दर्ज वृद्धि साल-दर-, जो ऑटोमोबाइल, खाद्य उत्पाद, विद्युत मशीनरी और रसायन क्षेत्रों द्वारा प्रेरित थी।
• IT companies' sales grew 7.8% (y-o-y) in Q2, up from 6.0% in the previous quarter.
• आईटी कंपनियों की बिक्री Q2 में 7.8% (साल(साल-दर- बढ़ी, जो पिछले तिमाही के 6.0% से अधिक थी।
• Non-IT services companies recorded 10.6% sales growth in Q2, up from 7.5% in the previous quarter.
• गैर ने कंपनियों सेवा आईटी-Q2 में 10.6% बिक्री वृद्धि दर्ज की, जो पिछले तिमाही के 7.5% से अधिक थी।

Ques: Who has been appointed as the Executive Director of Canara Bank for a tenure of 3 years?
कनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 साल के कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है?

A) Shri. Rajesh Kumar / श्री राजेश कुमार
B) Shri. Sunil Kumar Chugh / श्री सुनील कुमार चुग
C) Shri. Anil Kumar / श्री अनिल कुमार
D) Shri. Pankaj Singh / श्री पंकज सिंह

E) Shri. Ramesh Gupta / श्री रमेश गुप्ता

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• Shri. Sunil Kumar Chugh has been appointed as the Executive Director of Canara Bank for a tenure of 3 years.
• श्री सुनील कुमार चुग को कनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है।
• Prior to this appointment, he was serving as the Chief General Manager at Punjab National Bank.
• इस नियुक्ति से पहले वह पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य महाप्रबंधक)Chief General Manager) के पद पर कार्यरत थे।

About Canara Bank:

- Established : 1906
- HQ : Bangalore, Karnataka
- MD & CEO : K. Satyanarayana Raju
- Tagline : Together we can

Ques: According to an SBI report, implementing four labour codes in India may create how many jobs and boost consumption by how much?
SBI की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में चार श्रम संहिताओं को लागू करने से कितनी नौकरियाँ सृजित हो सकती हैं और उपभोग में कितनी वृद्धि हो सकती है?

A) 50 lakh jobs & ₹50,000 crore
B) 77 lakh jobs & ₹75,000 crore
C) 1 crore jobs & ₹1 lakh crore
D) 25 lakh jobs & ₹30,000 crore
E) 60 lakh jobs & ₹60,000 crore

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• SBI report states that implementing the four labour codes—Code on Wages (2019), Industrial Relations Code (2020), Code on Social Security (2020), and Occupational Safety, Health & Working Conditions Code (2020)—may create 77 lakh jobs and boost consumption by ₹75,000 crore.
• SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि चार श्रम संहिताओं को लागू करने से 77 लाख नौकरियाँ सृजित हो सकती हैं और उपभोग में ₹75,000 करोड़ की वृद्धि हो सकती है।
• The codes are expected to reduce unemployment from current 3.2% to a range of 1.9%–2.9% depending on scenario.
• इन संहिताओं से वर्तमान 3.2% बेरोजगारी को 1.9%–2.9% तक घटाने की संभावना है।
• All workers will become eligible for minimum wages under the Code on Wages, potentially increasing daily income by ₹95, leading to higher consumption after savings.
• वेतन संहिता के तहत सभी श्रमिक न्यूनतम वेतन के पात्र होंगे, जिससे दैनिक आय ₹95 बढ़ सकती है और बचत के बाद उपभोग में वृद्धि होगी।
• Formalisation of workforce expected to rise by 15.1%, reaching 75.5% of workforce in formal sector.
• कार्यबल का औपचारिकरण 15.1% बढ़ने की संभावना है, जिससे औपचारिक क्षेत्र में कार्यबल 75.5% तक पहुँच जाएगा।
• 44 crore workers in unorganised sector; 31 crore registered on e-Shram portal.
• 44 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं; 31 करोड़ e-Shram पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

Ques: Which bank signed a strategic partnership with Hub71 and the UAE–India CEPA Council to support Indian start-ups globally?
कौन सा बैंक हब71 और UAE–India CEPA काउंसिल के साथ भारतीय स्टार्टअप्स का वैश्विक स्तर पर समर्थन करने के लिए रणनीतिक साझेदारी में शामिल हुआ?

A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
B) First Abu Dhabi Bank (FAB) / फर्स्ट अबू धाबी बैंक
C) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
D) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
E) Axis Bank / एक्सिस बैंक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• First Abu Dhabi Bank (FAB) and Hub71, Abu Dhabi's global tech ecosystem, signed strategic partnerships with the UAE–India Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Council to accelerate cross-border entrepreneurship and support Indian start-ups to scale globally through the UAE.
• फर्स्ट अबू धाबी बैंक)FAB) और हब71, अबू धाबी की वैश्विक टेक्नोलॉजी ईकोसिस्टम, ने UAE–India CEPA काउंसिल के साथ रणनीतिक साझेदारी की, जिससे सीमा पार उद्यमिता को बढ़ावा मिले और भारतीय स्टार्टअप्स को UAE के माध्यम से वैश्विक स्तर पर विस्तार करने का समर्थन मिले।
• From a pool of start-ups, 20 outstanding companies were selected to showcase Indian innovation in New Delhi on November 25, with five chosen to expand globally using the UAE as their launchpad.
• स्टार्टअप्स के पूल में से 20 उत्कृष्ट कंपनियों को 25 नवंबर को नई दिल्ली में भारतीय नवाचार प्रदर्शित करने के लिए चुना गया, जिनमें से पांच को UAE को लॉन्चपैड बनाकर वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए चयनित किया जाएगा।
• The agreement was signed at the Abu Dhabi Investment Forum (ADIF) in Mumbai.
• यह समझौता मुंबई में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फोरम)ADIF) में हस्ताक्षरित किया गया।

Ques: What factors drove India's economic growth in October 2025 despite global challenges?
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अक्टूबर 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि को कौन से कौन-कारक बढ़ावा दे रहे थे?

A) GST rate rationalisation & festival spending / GST दरों का समायोजन और त्योहारी खर्च
B) High exports & low imports / उच्च निर्यात और कम आयात
C) Increased foreign direct investment / बढ़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
D) Decline in credit growth / ऋण वृद्धि में कमी
E) Reduction in government spending / सरकारी खर्च में कमी

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

• India's economic growth in October 2025 was driven by GST rate rationalisation and higher consumer spending during festivals.
• अक्टूबर 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि GST दरों के समायोजन और त्योहारी मौसम में बढ़े उपभोक्ता खर्च से प्रेरित थी।
• Reserve Bank of India (RBI) noted improvement in manufacturing and services sectors, with strong macroeconomic frameworks supporting the economy.
• भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में सुधार और मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक ढांचे की भूमिका का उल्लेख किया, जिसने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया।
• GST collections increased compared to the previous month, indicating a rise in consumer demand.
• पिछले महीने की तुलना में GST संग्रह में वृद्धि हुई, जो उपभोक्ता मांग में वृद्धि को दर्शाती है।
• Fiscal, monetary, and regulatory measures are expected to create a virtuous cycle of higher private investment, productivity, and growth.
• वित्तीय, मौद्रिक और नियामक उपाय उच्च निजी निवेश, उत्पादकता और वृद्धि का एक सकारात्मक चक्र उत्पन्न करने की उम्मीद है।
• Merchandise trade deficit reached an all-time high due to surging imports (gold & silver) despite export contraction.
• निर्यात में गिरावट के बावजूद आयात घाटा व्यापार वस्त्र से बढ़ोतरी में (चांदी और सोना) गया। पहुंच पर स्तर उच्चतम के तक अब

Ques: Which securities did SEBI propose to exclude from BSDA portfolio value calculation?
SEBI ने BSDA पोर्टफोलियो मूल्यांकन से किन प्रतिभूतियों को बाहर करने का प्रस्ताव रखा?

A) Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) bonds / ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल)ZCZP) बॉन्ड
B) Delisted securities / डीलिस्टेड प्रतिभूतियां
C) Suspended securities / निलंबित प्रतिभूतियां
D) Both A & B / दोनों A और B
E) Government securities / सरकारी प्रतिभूतियां

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

• SEBI proposed excluding Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) bonds and delisted securities from Basic Services Demat Account (BSDA) portfolio value calculation.
• SEBI ने BSDA पोर्टफोलियो मूल्यांकन से ZCZP बॉन्ड और डीलिस्टेड प्रतिभूतियों को बाहर करने का प्रस्ताव रखा।
• ZCZP bonds are non-transferable, non-tradable, and provide no monetary return, hence treated like social contribution, not investment.
• ZCZP बॉन्ड गैरहस्तांतरणीय-, गैरदेते नहीं लाभ मौद्रिक कोई और हैं योग्य व्यापार-, इसलिए इन्हें निवेश नहीं बल्कि सामाजिक योगदान माना जाता है।
• Delisted securities are proposed to be excluded similar to already-excluded suspended securities due to lack of price discovery and liquidity.
• डीलिस्टेड प्रतिभूतियों को निलंबित प्रतिभूतियों की तरह बाहर करने का प्रस्ताव है, क्योंकि इनमें मूल्य खोज और तरलता नहीं है।
• Illiquid securities will still be valued at last closing price. Reassessment of BSDA eligibility is proposed quarterly instead of varying billing cycles.
• तरल प्रतिभूतियों का मूल्य अंतिम बंद मूल्य पर रखा जाएगा। BSDA पात्रता का पुनर्मूल्यांकन तिमाही आधार पर प्रस्तावित है।
• SEBI suggests easier consent methods for investors preferring normal demat accounts.
• सामान्य डिमैट खाते चुनने वाले निवेशकों के लिए SEBI ने आसान सहमति चैनलों की सिफारिश की है।

EXAM Genius